MR. CHAIRMAN: Please take your seats. *...(Interruptions)...* एक मिनट आप बैठ जाइए, मेरी बात तो सुनिए ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसुः सवाल का जवाब होता है जानकारी प्राप्त करने के लिए। जानकारी न देने के लिए अगर सरकार जवाब देने के अधिकार को इस्तेमाल करती है तब उससे अफसोसनाक बात कुछ और नहीं हो सकती है और तब इस संसद की मर्यादा, जिसकी हिफाजत के लिए आपने पहले बयान दिया है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए। यह क्वेश्चन तो है नहीं, यह तो रेफरेंस है। चूंकि मंत्री महोदय यहां पर थे, तो उन्होंने जवाब दे दिया, अगर आपको कोई और जवाब चाहिए ...(**व्यवधान**)...पहले मेरी बात सुन लीजिए, जो भी जवाब उन्होंने दिया है, उससे if you are not satisfied, you are allowed to raise it again, when there is a chance.

श्री दीपांकर मुखर्जीः मेरे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। No, Sir. There is no question *{Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: No. Now, I would not allow you. *...(Interruptions)...* Now, I would not allow you. *...(Interruptions)...*

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: A corrected answer must come. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Excuse me, Mr. Mukherjee. *...(Interruptions)...* Now, I would not allow you. *...(Interruptions)...*

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा)**:** यह बोलने का आपका क्या अधिकार बनता है।

श्री सभापतिः आप बैठिए, बैठिए। मैं उसे देख लूंगा।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Then we should not have asked the question. *...(Interruptions)...*

श्री सभापतिः मैं उसे देख लूंगा।

Uncertainity prevailing over setting up of a National Institute of Science in Bubhaneswar

SHRI B.J. PANDA (Orissa): Sir, with your permission, I raise a matter which is agitating the people of Orissa and it is a grave matter.

If reports are to be believed, this Government at the Centre is playing regional politics and is *. It is not just*; it is giving affidavits in court which are nothing short of perjury. It relates to the National Institute of Science.

MR. CHAIRMAN: The word * will not go on record ...*(Interruptions)*... This word * will not go on record.

SHRI B.J. PANDA: Sir, it is misleading. In 2003, the then Government announced the establishment of four National Institutes of Science along the lines of the Indian Institute of Science which exists in Bangalore and the four centres announced were Chennai, Pune, Allahabad and Bhubhaneswar. The explicit purpose of this was to bring about regional equity in providing high quality scientific and technical education to the people of India, particularly, in Bhubhaneswar.

Sir, in the meantime, we have been shocked to note a newspaper report in The Statesman two months ago, in October, saying that two similar institutes are going to come up in Pune and Kolkata. There is no further news about what is happening to the NIS which are supposed to be set up in the four places, Pune, Bubhaneswar, Chennai and Allahabad. What is really agitating us is; that there are newspaper reports that the Government has made statements that there was no such plan and there was no such commitment to set up an NIS in Bhubaneswar.

Sir, I would like to highlight that here is a copy of the project report on the NIS from the UGC. Here, I have a copy of a letter from the UGC asking the Utkal University representatives to attend the meeting for planning the establishment and structures based on the detailed project report on the NIS to be set up in Bubhaneswar. There are reports that the Government has filed an affidavit in a PIL in the Orissa High Court that there was no such commitment to set up the NIS which is patently false because of the evidence we have got. There has also been a report that these Institutes which have been called IISCR are not the same as

*Not recorded.

the NIS which were proposed to be set up. it is again patently false because both are described similar to the Indian Institute of Science at Bangalore. ...*(Interruptions)*... One more minute, Sir. My point is that we have no problem, if something is to be set up in Pune or if something new is to be set up in Kolkata We have no problem with that. But what was already announced should not be taken away from Orissa. It must be set up in Orissa. These misleading statements are further compounded subsequent to the Government's misleading statements which have been reported in national newspapers. Here is a publicaiton brought out recently by the UGC. The UGC very specifically says that one of these four NISs is to be set up in Bhubaneswar. It is very specifically mentioned here. So, there is no question of no assurance having been there. I understand that the hon. Minister has, perhaps, given an assurance to the other House that the Government will respond to it. My request is, a similar assurance be given to this House that this commitment must be kept. They must assure that his commitment must be kept.

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): सभापति जी,

MR. CHAIRMAN: You can associate yourself.

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं एक वाक्य में एसोसिएट करना चाहती हूं कि जो विषय अभी पंडा जी ने उठाया है वह तर्क के साथ-साथ भावना का भी विषय है। तर्क के आधार पर तो उन्होंने पुष्ट करने के लिए सारे तथ्य आपको सामने, सदन के सामने रख दिए। लेकिन सभापति जी, अगर किसी एक व्यक्ति को भी दो रुपए देकर वापिस लेते हैं तो उसका मन विद्रोह करता है। यह पूरे के पूरे प्रदेश का मामला है। एक प्रदेश को एन.आई.एस. देकर आज केवल उससे छीना ही नहीं जा रहा है कोलकाता में बनाए जाने की घोषणा की जा रही है। जैसा पंडा जी ने कहा कि आप पांचवा बना दें कोलकाता में हमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर उड़ीसा का, भुवनेश्वर का वापिस लिया जाएगा तो उसका बहुत बड़ा विद्रोह होगा और इसलिए इस विद्रोह से सरकार को बचना चाहिए और यहां यह बात कहनी चाहिए कि भुवनेश्वर में बनाए जाने वाला, साथ-साथ में इलाहाबाद में बनाए जाने वाला यह दोनों एन.आई.एस. खुलेंगे, बनाए जायेंगे, इसका आश्वासन हमको मिलना चाहिए।

डा.मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): सर,

श्री सभापति: मैं एलाउ नहीं कर रहा हूं, आप एसोसिएट कर सकते हैं। मैं एलाऊ नहीं करुंगा। ...(**व्यवधान**)... आप सिर्फ एसोसिएट कर दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

associate yourself. ...*(Interruptions)*... Please go back to your seat. Go back to your seat. Take this Member to his seat. Let the Government respond to it. मैं एलाउ नहीं करुंगा ...(**व्यवधान**)... पहले उनका सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं बोल लूं, उसके बाद वे बोल लें। क्योंकि इलाहाबाद को भी यू.जी.सी. ने दिया था। यू.जी.सी. ने चार स्थानों पर इसको स्थापित करने की बात कही थी और उद्देश्य यह था उस समय जिस प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस दक्षिण के अंदर एकमात्र संस्था सारे देश में है, हमारे देश में चार-पांच संस्थाएं होनी चाहिए इतने बड़े देश में और इसके लिए चार स्थानों पर तय किया था यूजीसी ने। किस कारण से आपने हटा दिया, केवल आप इसलिए कि उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में आप हटाएंगे, पूना में आप रखेंगे। कोलकाता में आप नया खोल लें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ...(**व्यवधान**)... लेकिन यह भेदभाव के कारण ...(**व्यवधान**)... यह सरकार की बहुत गलत नीति है। ...(**व्यवधान**)... कोलकाता में पांचवां खोल लें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सभापति : ठीक है, आपका पोइंट आ गया। The matter is over.

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा)**:***

श्री सभापति: इनका रिकार्ड पर नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)... कोई रिकार्ड पर नहीं जा रहा है ...(**व्यवधान**)...

श्री सीताराम येचुरी (पश्चिमी बंगाल)**:** सर, हम इसके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी के पास, उड़ीसा के हमारे लोगों का मैं एक डेलीगेशन ले गया था, यह कहते हुए कि जो यह आश्वासन पहले दी गई वह नेशनल इंस्टीट्यूट आफ साइंस वहां पर खुलना चाहिए और हम चाहते हैं कि हम भी इसके साथ एसोसिएट करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि:*

श्री सभापति: आपका रिकार्ड पर नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, इनको बन्द करिए वरना मुझे एक्शन लेना पड़ेगा मेरी टोलरेंस को चेलेंज मत करिए, मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)... आप भी बोलें, और भी बोलें सब ने एसोसिएट किया है। ...(**व्यवधान**)...

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री सुरेश पचौरी**): सम्मानित सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री पंडा जी और उनके साथ अन्य सदस्यों ने साइंस इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में खोले जाने संबंधी विषय को उठाया है। यह

*Not recorded.

मामला बहुत भावुक है और इसके साथ माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने भी सम्बद्ध किया है और इलाहाबाद का अल्लेख किया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मुझे जो जानकारी एच.आर.डी. मिनिस्ट्री ने दी है, उसके अनुसार और तत्कालीन एन.डी.ए. सरकार के पूर्व भी कुपापूर्वक यहां उपस्थित हैं, वे शायद इसकी पुष्टी करें कि यूनिवर्सिट्स भुवनेश्वर, इलाहाबाद, चेन्नै और पुणे में खोले जाने चाहिए। इस निर्णय को यू.जी.सी. ऐक्ट के सैक्शन 12 का पालन करते हुए लिया गया था। बाद में उसी सरकार ने, यानी एन.डी.ए. सरकार ने 9 जून, 2003 को मिनिस्ट्री ऑफ ला एंड जस्टिस से यह जानना चाहा कि क्या यू.जी.सी. ऐक्ट के सैक्शन 12 का पालन करते हुए यू.जी.सी. को यह अधिकार है कि वह इस प्रकार के निर्णय लें? बाद में उसी सरकार के दौरान 28, अक्टूबर 2003 को यह बताया गया कि यू.जी.सी. ऐक्ट के सैक्शन 12 के तहत जो निर्णय लिया गया है, उसके तहत ये सेंटर्स खोलने के लिए वह empowered नहीं था, इसलिए यह materialise नहीं किया जा सकता। मैं नहीं जानता कि यह सही है या नहीं लेकिन जो कागज मुझे दिए गए, उनके अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा यह बताया गया कि यह उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जिस प्रोजेक्ट का आपने हवाला दिया, यह सही है कि उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था। यह भी सही है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने निर्णय लिया था। अब दूसरा पार्ट यह है कि साइंटिफिक एडवाइज़री काउंसिल, जो प्राइम मिनिस्ट्र के साथ सम्बद्ध है, उसकी 4 मार्च, 2005 को एक मीटिंग हुई और उसने दो नए इंस्टिट्यूट खोलने का निर्णय लिया। उसने यह निर्णय नहीं लिया कि वह इंस्टीट्यूट यदि खुला था, तो उसको बंद किया जाना चाहिए, बल्कि उसने यह निर्णय लिया कि पुणे और कोलकाता में भी इंस्टिट्यूट खोले जाएं। तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि क्या उस एन.डी.ए. की सरकार के दौरान ऐसा निर्णय लिया गया था, यू.जी.सी. के द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा कि ये इस्टीट्यूट वहां खोले जाएं और यदि ऐसा इंस्टीट्यूट वहां खोले जाने संबंधी निर्णय लिया गया, तब सरकार इस पर सकारात्मक प्रक्रिया व्यक्त करने में कभी हिचकिचाएगी नहीं। दूसरा, जो पुणे और कोलकाता का निर्णय लिया गया है, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि उस निर्णय पर सरकार अभी भी वचनबद्ध है, लेकिन इस निर्णय को इस आधार पर नहीं लिया गया कि पहले दूसरी जगह यदि सरकार ने कोई निर्णय लिए हैं, तो उन स्थानों से स्थानांतरित किया जाए, फिर भी मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि मान्यवर, यह जो मैं बोल रहा हूं, यह क्योंकि आपने मुझे कहा था कि मैं वस्तुस्थिति प्राप्त कर लूं, फिर भी मैं माननीय सदस्यों की भावना से जो संबंधित मंत्रालय है, उनको अवगत करा दूंगा। यदि कोई ऐसी व्यवस्था निकलती है कि भुवनेश्वर में, जो निर्णय इनके कार्यकाल में, इनकी सरकार के द्वारा नहीं लिया जा सका, केवस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा लिया गया, यदि वह मंजूरी लायक हो सकता है तो ...(**व्यवधान**)...

SHRI B.J. PANDA: We are not satisfied...*(Interruptions)*
MR. CHAIRMAN: Mr. Panda, please take your seat.. *(Interruptions)*

एक मिनट...एक मिनट...माननीय ...(**व्यवधान**)... एक मिनट. आप बैठ जाइए।

SHRI B.J. PANDA: We cannot accept this...*(Interruptions)* This is not acceptable to us...*(Interruptions)*

श्री सभापतिः माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करुंगा ...(**व्यवधान**)... आप एक मिनट बैठ जाइए। मैं एलाऊ नहीं कर रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, आपने जवाब दिया, यह ठीक है। जैसे अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर बोल रहे थे कि आपको राज में नहीं हुआ, हमने अब किया है। मान लीजिए उस समय, जैसे आपने कहा कि यदि वह खुला है, तो खोल दिया जाएगा। नहीं भी खुला है, तो खोलने में क्या आपत्ति है?

श्री सुरेश पचौरीः सर, मैं यह कमिटमेंट यहां नहीं दे सकता, यह संबंधित विभाग ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः ठीक है, मगर आप ध्यान में रखिए।

श्री सुरेश पचौरीः मैंने यह कहा कि मैं सदन की भावना से माननीय मंत्री जी को अवगत करा दूंगा।

श्री सभापतिः आप ध्यान में रखिएगा। ...(**व्यवधान**)... बस ठीक है ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः नहीं सर, सवाल यह है कि ...(व्यवधान)...

SHRI B.J. PANDA: This is not replacement for those institutes. *(Interruptions)* पुणे में क्या दो आएंगे? पुणे में तो दो नहीं आएंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः अगर यू.जी.सी. ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please take your seats. *(Interruptions)* The matter is over. *(Interruptions)* Next Shri Ravula Chandra Sekar Reddy. *(Interruptions)*

SHRI B.J. PANDA: Sir, the Government is avoiding the issue. *(Interruptions)*

श्री सभापतिः मैं ने आपको एलाऊ किया है। ...(**व्यवधान**)... अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि

श्रीमती सुषमा स्वराजः सर, प्रश्न यह है कि ...(**व्यवधान**)... सरकार है। ...(**व्यवधान**)... वेस्ट बंगाल में सीपीएम की सरकार है। ...(**व्यवधान**)... इसाहाबाद में इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि

वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार है। ...(**व्यवधान**)... भुवनेश्वर में इसलिए नहीं खुल रहा है कि ...(**व्यवधान**)... यू.जी.सी. की सरकार है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI B.J. PANDA: Sir, this smacks of regional favouritism. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. *(Interruptions)* Mr. Panda, I request you to take your seat. You have brought the matter to the notice of the Government. The Government has reacted and there are chances... *(Interruptions)*

श्री एस.एस.अहलुवालिया (झारखंड): सभापति महोदय, क्या यह बताने की कृपा करेंगे ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... मैं एलाऊ नहीं कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

Nothing will go on record. *(Interruptions)* Please take your seats ...(**व्यवधान**)... देखिए कोई रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। ...(**व्यवधान**)... कोई रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। ...(**व्यवधान**)... कोई रिकार्ड पर नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)... आप इस विवाद में क्यों पड़ रहे हो? ...(**व्यवधान**)... आपने अपना मैटर रेज कर दिया। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट ठहर जाइए। आपने अच्छी तरह से रेज कर दिया है। गवर्नमेटं ने इस पर अपना रिएक्शन दे दिया। ...(**व्यवधान**)... आप मेरी बात तो सुनिए। ...(**व्यवधान**)... आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं एलाऊ नहीं करुंगा। ...(**व्यवधान**)... कोई एक शब्द भी रिकार्ड पर नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)...वह समझ में आ गई है। ...(**व्यवधान**)... जो भेदभाव किया है, वह बाद में देखेंगे। ...(व्यवधान)... चलिए, श्री रावूला चन्द्रशेखर रेड्डी। ...(**व्यवधान**)... Only his speech will go on record. *(Interruptions)*... ठीक है, ठीक है, चलिए। ...(**व्यवधान**)... आप कहां मुकाबले पर खड़े हो गए? ...(**व्यवधान**)... चलिए, रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी।

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

Appalling condition of farmers of Anantapur district in Andhra Pradesh

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, this is a problem of farmers of Anantapur District of Andhra Pradesh, wherein more than 20 lakh acres of groundnut crop was washed away due to unprecedented rain during the months of October and November,